



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 वैशाख 1945 (श0)
(सं0 पटना 406) पटना, बुधवार, 17 मई 2023

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन निदेशालय)

अधिसूचना
15 मई 2023

सं० 14/डी0एल0ए0—(प्राधिकार)—नियुक्ति-01/2022-676/रा0—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 (RFCTLARR Act-2013) के अध्याय-VIII की धारा-51 के अंतर्गत समुचित सरकार (Appropriate Government) द्वारा अधिसूचना जारी कर भू-अर्जन संबंधी मुआवजा भुगतान, पुनर्वास एवं पुनःस्थापन से संबंधित विवादों के त्वरित निपटारे तथा अधिनियम की धारा-64(1) के अंतर्गत निर्देश मामलों (Reference cases) की सुनवाई हेतु एक या अधिक भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार (Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Authority) की स्थापना का प्रावधान है।

2. बिहार भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियमावली-2013 के नियम-35 के तहत राज्य के प्रत्येक राजस्व प्रभाग के मुख्यालयों यथा—पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सारण, मुंगेर, सहरसा, पूर्णिया, गया एवं भागलपुर में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार की स्थापना, उसे प्रदत्त अधिकारिता, शक्ति एवं प्राधिकार का प्रयोग करने के लिए की गई है। पीठासीन पदाधिकारी (Presiding Officer) प्राधिकार के अध्यक्ष होंगे।

3. प्राधिकार के पीठासीन पदाधिकारी की नियुक्ति हेतु राजस्व विभागीय आदेश सं०-289/रा०, दिनांक-27.02.2023 द्वारा गठित चयन समिति की बैठक दिनांक-07.03.2023 में लिये गये निर्णय के तहत सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं समकक्ष की संधारित मेधा सूची के अनुसार भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार, मुंगेर के पीठासीन पदाधिकारी के पद पर श्री मनोज कुमार-I, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, किशनगंज को नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है।

4. श्री मनोज कुमार-I, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/न्यायिक पदाधिकारी को भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार, मुंगेर के पीठासीन पदाधिकारी के पद पर उनके पदग्रहण की तिथि से तीन वर्ष अथवा 65 वर्ष आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले घटित हो, नियुक्त किया जाता है।

5. विभागीय अधिसूचना सं०-484/रा० दिनांक-07.04.2016 द्वारा स्थापित प्रत्येक प्राधिकार की अधिकारिता एवं कार्यक्षेत्र संबंधित प्रमंडल के अधीनस्थ सभी जिलों में होगी। बिहार भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियमावली-2014 के नियम 36 के अंतर्गत प्राधिकार को झूठे दावों इत्यादि के माध्यम से लिये गये पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन लाभों की वसूली की शक्ति होगी।

6. प्राधिकार के पीठासीन पदाधिकारी के वेतन एवं भत्ते उनकी सेवानिवृत्ति के समय उनके द्वारा अंतिम आहरित पारिश्रमिक, घटाव पेंशन के समतुल्य होगा। इसके अतिरिक्त, वे अपना पेंशन एवं स्वयं पर लागू संबंधित नियमों के अधीन प्रोद्भूत अन्य लाभ आहरित करेंगे।

7. पीठासीन पदाधिकारी की अन्य सेवा शर्तें वही होगी जो बिहार राज्य में कार्यरत जिला न्यायाधीश पर लागू होंगे। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा समय-समय पर निर्गत एतद् संबंधी पत्र/परिपत्र के प्रावधान प्रभावी होंगे।

8. पीठासीन पदाधिकारी के वेतनादि से संबंधित व्यय भार मुख्य शीर्ष 2029 भू-राजस्व 001 निदेशन और प्रशासन 0004 भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार मांग सं०-40 विपत्र कोड संख्या-एन 2029000010004 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

9. पीठासीन पदाधिकारी का वेतनादि भुगतान राजस्व विभागीय ज्ञापांक-1291/रा० दिनांक-20.11.2015 द्वारा पीठासीन पदाधिकारी के सृजित स्थायी पदों के विरुद्ध किया जायेगा तथा राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी। इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राधिकार के अधीन कार्यरत निबंधक (Registrar) होंगे।

10. श्री मनोज कुमार-I, को निदेशित किया जाता है कि वे अपने पदस्थापन कार्यालय में अपना योगदान नियुक्ति पत्र प्राप्ति की तिथि के सात दिनों (एक सप्ताह) के भीतर देना सुनिश्चित करेंगे।

11. यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुशील कुमार,
निदेशक, भू-अर्जन-सह-अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 406-571+300-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>